

आकाशवाणी गोरखपुर
प्रादेशिक समाचार

दिनांक-14 जुलाई 2024

7:20 AM

पहले मुख्य समाचार।

- प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्र चूड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा, मुख्य न्यायाधीश ने क्षेत्रीय भाषाओं में कानून की शिक्षा पर दिया जोर ।
- प्रदेश में सोलह जिले बाढ़ से प्रभावित, अलग अलग स्थानों पर सात नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर ।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को दी चेतावनी-डग्गामार या बिना परमिट बस चलती मिली तो होगी कार्रवाई ।
- प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोक अदालतों का आयोजन, सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हुए मुकदमे ।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि यदि कानून के सिद्धांतों को आम जनता को सरल शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है, तो कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा में कमी है। लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने क्षेत्रीय भाषाओं में कानून की शिक्षा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को डिग्रियां प्रदान की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैंने ऐसे कई निर्देश दिये हैं स्कीम बनाई है जिससे न्याय की प्रक्रिया को आम लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का, भारत के संविधान में प्रचलित विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। जिससे आम जनता भी समझ सकें कि निर्णयों में आखिर लिखा क्या गया है। आज 1950 से लेकर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय के 37 हजार निर्णय हैं रिपोर्ट इंटरवेंशन है सारे 37 हजार जजमेंट का हिन्दी में अनुवाद हो गया है।

श्री चन्द्रचूड़ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने न्याय प्रक्रिया को आम लोगों के लिए और अधिक सुलभ बनाने के लिए कई निर्देश जारी किये हैं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बार और बेंच का बेहतर समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। एक आम जनमानस अधिवक्ता के पास एक उम्मीद लेकर आता है। किसी व्यक्ति से अधिवक्ता जहां कहीं भी साइन करने के लिए कहता है, वह साइन कर देता है, क्योंकि उसको विश्वास है और यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह विश्वास सामान्य नागरिक का बार और बेंच दोनों पर बना रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सुशासन की पहली शर्त, विधि का शासन है।

सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन, न्याय संगत व्यवस्था और न्याय समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। रिसेप्शन गवर्नेंस आमजन की भावनाओं को बदलने के लिए देश और दुनिया की धारणा बदलने के लिए अत्यन्त बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इस अवसर पर इन विद्यार्थियों को आज उनकी डिग्रियाँ अवार्ड की गयीं हैं मैं सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूँ।

कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अमरपाल सिंह और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।

बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के सोलह जिलों में बाढ़ का प्रभाव बना हुआ है। इनमें लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, गोरखपुर, आजमगढ़, हरदोई, अयोध्या, गोंडा और बहराइच जिले शामिल हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा कल शाम जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की सात नदियां अलग अलग स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ को देखते हुए संबंधित जिलों के प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अधिकारी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति पर नजर बनाये हुए हैं। गोरखपुर में जिलाधिकारी ने एसडीएम और तहसीलदार को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों को राहत कैम्प में पहुंचाने के निर्देश दिये हैं। हरदोई में जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों तैनात करने को कहा है, ताकि बीमार लोगों को तत्काल मदद मिल सके।

नीट पेपर लीक मामले में हजारी बाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल अहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज समेत 4 आरोपियों को सीबीआई की रिमांड पूरी होने पर पटना के बेउर जेल भेज दिया गया है। कल सीबीआई की टीम पटना में 13 आरोपियों को बेउर जेल से पूछताछ के लिए ले गई, जहां सभी से अलग-अलग पूछताछ की जाएगी।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में शामिल संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आवेदन आमंत्रित किये हैं। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि पुरस्कार का उद्देश्य दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले संगठनों को सशक्त बनाना और प्रोत्साहित करना है। इसके लिए इस महीने की 31 तारीख तक आवेदन भरे जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में सड़कों पर डग्गामार या बिना परमिट की कोई बस चलती मिली तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ कल बैठक में निर्देश दिया कि प्रदेश में चल रही सभी यात्री बसों और स्कूल बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की गहनता से जांच की जाए।

मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में एक माह तक डग्गामार और बिना परमिट वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान के निर्देश जारी कर दिये हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कल अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंच कर श्रीरामलला का दर्शन पूजन किया। उन्होंने भगवान राम को बेर भी चढ़ाए। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है। भगवान राम का ननिहाल है। मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ से बेर, वहां का जल, सुगंधित चावल और कई अन्य प्रकार का प्रसाद भगवान राम को अर्पित किया।

कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में कल सहारनपुर के सरसावा एयरफोर्स स्टेशन में पहली बार एयर-शो हुआ। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट—

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने सहारनपुर में सरसावा वायुसेना स्टेशन पर कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहीदों के परिवारवालों को सम्मानित भी किया गया। सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एयर शो में मारक क्षमता वाले जेट विमानों ने अपने करतब दिखाए। एयर शो के दौरान आकाशगंगा टीम के कमांडो 10 हजार फीट की ऊंचाई से उतरे। एयर शो में जगुआर और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों समेत एमआई 17 हेलीकॉप्टर्स ने अपने हैरतअंगेज स्टंट दिखाए। एयर शो में वायु सेना के शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन देखकर हजारों की संख्या में उपस्थित एनसीसी कैडेट्स, स्कूली बच्चों और नागरिकों ने रोमांचित महसूस किया। विजयंत सैनी, आकाशवाणी समाचार, सहारनपुर।

प्रदेश के अलग अलग जिलों में कल लोक अदालतों का आयोजन कर मुकदमों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। कासगंज जिले में जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सैय्यद मारुज बिन आसिम, नोडल अधिकारी घनेंद्र कुमार और सचिव विजय कुमार ने लोक अदालत का शुभारंभ किया। सचिव ने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के शमनीय वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। इस अवसर पर वहां स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। मेरठ जिले में आयोजित लोक अदालत के दौरान परिवार न्यायालय में दो सौ दस मुकदमे आए जिनमें से एक सौ तिरासी का निस्तारण किया गया। वहां की अपर प्रधान न्यायधीश (परिवार न्यायालय) बीना नारायण और पुष्पा सिंह ने बताया कि लोक अदालत में परिवार व पति पत्नी को समझा कर आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण भी होता है। मिर्जापुर जिले में वहां के जिला न्यायाधीश अनमोल पाल ने लोक अदालत का उद्घाटन किया। बस्ती जिले में पचासी हजार एक सौ पंद्रह, उन्नाव में सड़सठ हजार चार सौ बारह, मऊ में सैंतालीस हजार सात सौ चौतीस और हरदोई में दस हजार आठ सौ चालीस वादों का लोक अदालत में निस्तारण किया गया।

शासन ने प्रदेश में छह जिलों के पुलिस कप्तान समेत दस आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। साथ ही देर रात पांच जिलों के डीएम समेत ग्यारह आईएएस अधिकारियों का भी स्थानान्तरण कर दिया गया
